पत्रांक-7 / सू0अ0 -05-03 / 2011 का -झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभागन

महोदय,

फिदेलिस टोप्पो,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 12/9/2011

झारटा<sup>ई</sup>ड लोक सेवा आयो ELEN CHARLE

1 5 SEP 2011

नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्र संख्था-3557, दिनांक 18.10.2005 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संख्या—B.C.-16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I, दिनांक 22.02.1985 की प्रति संलग्न फरते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किया गया था। इस क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र संख्या— 27/26/2006-SRS, दिनांक 29 जुलाई, 2008 प्राप्त हुआ है। पत्र में अंकित अनुदेश के अनुसार नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तभी दी जा सकती है जब उम्मीदवार की जाति राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा

अनुरोध है कि नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त तदनुसार कार्रवाई की जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की प्रति भी संलग्न है।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

Letters-7

सरकार के संयुक्त सचिव।

उम्मीदवार राज्य का अधिवासी (Domicile) हो।

DAttenton Sho Shukla

No.27/26/2006-SRS Ministry of Personnel, P.G. & Pensions ( Department of Personnel & Training ) Government of India

Τo

Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003. Dated: 28th July, 2008

**2008** 2008

Sh. N. S. Napalchayal, Principal Secretary, Reorganisation, Government of Uttrakhand, Dehradun.

Dr. R.C. Srivastava, Principal Secretary, Uttar Pradesh State Re-organisation Coordination Department, Vikas Bhavan, Janpath, Lucknow, Uttar Pradesh.

Subject : Consideration of representations of the employees of reservation category where their caste is listed only in one of the successor State regarding.

Sir,

I am directed to say that the reference received from the National Commission for Schedule Tribes on the above mentioned issue has been examined in consultation with the Reservation Division of this Department. The Reservation Division has stated that the benefits of reservation in the matter of appointment to post or admission in educational institutions is available only to State candidates who belong to a caste / community which is categorised as SC / ST / OBC of the State and who are the 'domicile' of It has recommended for allocating such candidates to the successor State where his caste is listed in the schedule, as per his option.

Keeping the advice of the Reservation Division in view, it has been decided to treat the employees, whose caste has been categorized as SC /ST /OBC only in one of the successor States, as special category, and all future allocation of these employees is to be made only to that State where their caste is listed in the schedule of the State or as per their option.

Yours faithfully,

Deputy Secretary to the Government of India

Tele.Fax:011 2462 3711

बारो किया/ISSURD Market Sig.

197 Laure Section